मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.292

08 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

रियल एस्टेट परियोजनाएं

292. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री जगन्नाथ सरकार:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा न होने और उनका आवंटन न होने के कारण फ्लैट बुक करने वाले प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा न होने और उनका आवंटन न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भू-सम्पदा परियोजनाओं का डेटा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। गृह-खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए और भू-सम्पदा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भू सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) बनाया है। रेरा के प्रावधानों के तहत, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण को भू-सम्पदा परियोजनाओं और रेरा के तहत पंजीकृत भू-सम्पदा एजेंटों को पंजीकृत और विनियमित करना आवश्यक है। विनियामक प्राधिकरण को पंजीकरण प्रदत्त सभी भू सम्पदा परियोजनाओं के आवश्यक विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने और व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता है।

(घ): अवरुद्ध परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत देने के लिए, गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित या दिवाला और दिवालियापन संहिता (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी

कोड) के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही वाली परियोजनाओं सहित, रेरा के तहत मूल्यवान और महत्वपूर्ण तथा पंजीकृत अवरुद्ध परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, किफायती और मध्यम-आय वाले आवास को पूरा करने के लिए एक विशेष विंडो (स्वामीह निवेश कोष) बनाई गई है। 30 नवंबर, 2022 तक, स्वामीह के तहत, 28,393 करोड़ रुपयों के कुल 286 सौदों को मंजूरी दी गई है और इससे लगभग 1,72,467 घर खरीदारों को लाभ होगा और 76,535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

******